श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है 'आयुष्मान भारत योजना', जिसके अंतर्गत अभी तक 55 करोड़ नागरिकों और 12.34 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। इस योजना से "स्वस्थ भारत, समर्थ भारत" को बढ़ावा मिल रहा है। 'आयुष्मान भारत योजना' दुनिया की सबसे बड़ी Centrally sponsored scheme है, जो अमेरिका में शुरू की गई 'ओबामा केयर' से भी बड़ी योजना है। इस योजना में प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य आश्वासन मिलता है। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस है एवं पूरे देश में पोर्टेबल भी है। इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें परिवार के आकार या उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं है। इसमें योजना पात्र लाभार्थियों की संख्या 2011 के 'Socio Economic Caste Census (SECC) के आधार पर तय की जाती है तथा इस योजना का पंजीकरण स्वत: ही राशन कार्ड के आधार पर होता है। यह census का data पुराना होने के कारण इस योजना से अभी भी कई गरीब परिवार वंचित रह गए हैं, क्योंकि जब भी वे कार्ड बनवाने जाते हैं, तो SECC में नाम न होने के कारण उन्हें आयुष्मान कार्ड नहीं दिया जाता है।

अत: मैं सरकार से माँग करता हूँ की इस योजना से छूटे हुए या वंचित गरीब लोगों को इस योजना में शामिल करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या नहीं बन पाए हैं और वे पात्र भी हैं, उनको भी इस योजना में शामिल करने के लिए प्रावधान किए जाएँ, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member, Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), associated herself with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Sanjay Seth.

5.00 P.M.

Demand for a comprehensive program to create awareness about food adulteration

श्री संजय यादव (बिहार): खाद्य उत्पादकों, खाद्य विक्रेताओं, आम नागरिकों, खाद्य निर्माताओं और खाद्य कंपनियों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों में मिलावट से उनके स्वास्थ्य को होने वाले खतरों के बारे में पूरी तरह से जागरूक किया जा सके। साथ ही, खाद्य उत्पादकों, प्रसंस्कृत खाद्य निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं को भी कड़े कानूनों और निरंतर पर्यवेक्षण से रोका जाना चाहिए, ताकि वे खाद्य पदार्थों को रसायनों, हानिकारक लवणों, योजकों, अत्यधिक चीनी और चमक देने वाले रसायनों एवं परिरक्षकों से भरने के बारे में दो बार सोचें।

खाद्य उत्पादों के स्वाद, रूप, बिक्री और शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए इन रसायनों के बड़े पैमाने पर उपयोग से लोगों के जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियाँ होती है। हम अपनी मेजों और प्लेटों में आने वाले प्रत्येक खाद्य उत्पाद में मिलावट के प्रति आंखें नहीं मूंद सकते। देश भर

में ऐसे जागरुकता अभियान एवं कार्यक्रम चलाए जाएं, जिससे लोग स्वयं यह पता लगाने में सक्षम हो जाएँ कि किस- किस प्रकार के खाद्य पदार्थ उनके लिए हानिकारक हैं। इसके साथ ही साथ, ऐसे हेल्पलाइन नंबर अथवा शिकायत करने के फ़ोरम उपलब्ध हों, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई मिलावट अथवा छेड़छाड़ करने वालों एवं स्वाद बढ़ाने के लिए हानिकारक पदार्थों के अनुचित उपयोग के विरुद्ध लोग बिना अपनी जानकारी दिए शिकायत दर्ज कर सकें, ताकि इस तरह की मिलावट की हर संभावना को जड़ से मिटाया जा सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by hon. Member, Shri Sanjay Yadav: Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Haris Beeran (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala) and Shri P.P. Suneer (Kerala).

Demand to establish Sports Injury Centre and Urology Department and augment facilities of Meerut Medical College, Meerut at par with other national level hospitals

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): लाला लाजपतराय मेडिकल कॉलेज, मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिकित्सा का केंद्र है। इस मेडिकल कॉलेज में 52 एकड़ जमीन रिक्त पड़ी हुई है। वहां कुछ बीमारियों के गंभीर मरीजों के इलाज की व्यवस्था न हो पाने के कारण इन 14 जिलों के मरीज दिल्ली के लिए रेफर किए जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर दिल्ली एम्स सहित दिल्ली के अन्य अस्पतालों में आते हैं। इस बोझ को कम करने की दृष्टि से मैं भारत सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरठ मेडिकल कॉलेज, मेरठ को पीजीआई में परिवर्तित किया जाए एवं इस कॉलेज को एम्स हॉस्पिटल का सैटलाईट सेंटर बनाया जाए तथा वहाँ यूरोलॉजी विभाग की भी स्थापना की जाए।

मेरा यह भी आग्रह है कि यहाँ कैंसर इंस्टिट्यूट की स्थापना किये जाने पर भी विचार किया जाए, जिसमें प्राथमिकता के तौर पर सामान्यतः कैंसर के परीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पहली स्टेज या दूसरी स्टेज पर मरीज को जानकारी हो जाए और उसकी जान बच सके, क्योंकि मरीज को सामान्यतः तीसरी और चौथी स्टेज में जानकारी होती है, जिस कारण उसको बचाना असंभव हो जाता है।

इस संबंध में मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ स्पोर्ट्स इंजरी का विभाग भी खोला जाए, ताकि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के अभ्यास के दौरान चोटिल होने पर यहाँ चिकित्सा सुविधा मिले।

मैं इस संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जनहित से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरतापूर्वक अनुकूल निर्णय हो सके, इस दृष्टि से विचार करें।